अमेरिका और जर्मनी 64 टैंक भेजेंगे यूक्रेन के लिए

अमेरिका इसी सप्ताह 50 अब्राम टैंक व जर्मनी 14 लैपर्ड-2 टैंक देने की तैयारी कर रहे हैं

वाशिंगटन, 25 जनवरी (वार्ता)। अमेरिका यूक्रेन को 50 एम1 अब्राम्स टैंक भेजने की योजना बना रहा है और वह बुधवार को इस संबंध में घोषणा कर सकता है। वहीं जर्मनी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुये 14 लैपर्ड-2 टैंक भेजने की घोषणा कर दी है। तुर्की की समाचार एजेंसी ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका युद्धग्रस्त देश यूक्रेन को मदद के रूप में इस सप्ताह अमेरिका एम1 अब्राम्स टैंकों को भेजने के फैसले की घोषणा कर सकता है। घोषणा कथित तौर पर जर्मनी के साथ एक व्यापक सौदे का हिस्सा होगी, जो यूक्रेन को अपने लेपर्ड 2 टैंकों की एक छोटी संख्या की आपूर्ति करेगा। अमेरिकी रक्षा विभाग 'पेंटागन' के प्रेस सचिव पैट राइडर ने बताया कि यूक्रेन ने रूस का सामना करने के लिए पश्चिमी देशों से कम से कम तीन सौ टैंक भेजने का अनुरोध किया है। अब्राम्स टैंक जटिल वाहन हैं जिन्हें उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है।

राइडर ने हालांकि इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि अब्राम्स टैंकों को चलाने के लिए क्या अमेरिका उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

गौरतलब है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान शुरू कर दिया था, जिसके बाद से पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए अपना सैन्य समर्थन बढ़ा दिया है। मॉस्को ने नाटो सदस्य देशों को अप्रैल में एक नोट भेजा, जिसमें कीव को उनकी सैन्य सहायता की निंदा की गई थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि यूक्रेनी क्षेत्र में हथियार की कोई भी खेप रूसी सेना के लिए "वैध लक्ष्य" होगी। जर्मनी ने बड़ी घोषणा की है। जर्मनी ने अपनी पिछली स्थिति से यू-टर्न लेते हुए कहा है कि यूक्रेन में अपने 14 टैंक भेजने और दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देने के लिए वह तैयार है।

'बदहाल पाकिस्तान की जनता की गुहार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी थोड़ा बढ़ी है, लेकिन उसकी यह आर्थिक वृद्धि कुछ ऐसी है जिसका कुछ हताश देशभक्त और वॉट्स ऐप पर बिना सोचे-समझे मैसेज भेजने वाले लोग ही उत्सव मना रहे हैं। पाकिस्तान की जी.डी.पी. करीब 350 बिलियन डॉलर है। आकार के हिसाब से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के दसवें हिस्से के बराबर है। आर्थिक समानता का यदि पहले कभी कोई भ्रम था तो वह दूर होना शुरू हो गया है। भारत के आर्थिक विकास की कहानी अभी शुरू ही हुई है पिछले दो दशकों की भारत की आर्थिक प्रगति पाकिस्तान का संचालन करने वाले चतुर लोगों को भयभीत करने में सफल रही है, ये लोग अब दिखाई नहीं दे रहे हैं।

मॉर्गन स्टेनले की भविष्यवाणी है कि वर्ष 2030 तक या सात वर्ष से कम समय में भारत की जी.डी.पी. वर्तमान 3.18 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 8 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। खुशी की यह ऐसी बात है जिसके लिए भविष्यवाणी के डेटा पर बार-बार गौर करने की जरूरत है। कुल वैश्विक निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्तमान में 2.2 प्रतिशत है। मॉर्गन स्टेनले को उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो जाएगी। भारत के खुदरा बाजार के इन अगले सात वर्षों में दोगुने से अधिक होकर 1.8 ट्रिलियन हो जाने की उम्मीद है।

शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जी.डी.पी. के प्रति व्यक्ति आंकड़े के 2 हजार 278 डॉलर प्रति वर्ष से बढ़ कर 5 हजार 242 डॉलर प्रति वर्ष हो जाने की उम्मीद है। भारतीय परिवार की वर्तमान में वार्षिक आय 35 हजार डॉलर है, इसके 5.6 प्रतिशत से बढ़ कर 25 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि प्रत्येक चार भारतीय परिवारों में से एक परिवार ग्लोबल मिडिल क्लास होम बन जाएगा। इसमें रहने वाले अधिकांश लोग उच्च शिक्षित होंगे जो उस परिवार के लिए धनार्जन करेंगे। उनमें से अधिकांश विलासिता की वस्तुओं के उपभोक्ता होंगे। पृथ्वी पर इण्डियन सैलीब्रिटीज को सर्वाधिक भुगतान किया जाएगा क्योंकि भारत के अपर मिडिल क्लास ही दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता होंगे। भारत गरीबों के देश से एक ऐसा देश बनने जा रहाहै कि वर्ष 2030 में पूरी अर्थव्यवस्था के समानांतर यहां पर बहुत से अमीर लोग होंगे। "भारतीय होने" को पवन वर्मा जैसे लेखकों ने एक बार परिभाषित किया था कि यह "अस्तित्व संबंधी विरोधाभास" से परिपूर्ण है।

अगले साल वर्षों या उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था इस खाई को पाट देगी। अधिक आय, अधिक सम्पन्नता और अधिक उपभोग "भारतीय होने" की उक्त धारणा में ठोस परिवर्तन लाएगा।

'सुप्रीम कोर्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संबंधित हो। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, "विधि मंत्री किरेन रिजीजू कोलीजियम पर हमला करते हुये यह क्यों कह रहे हैं कि उसने जज की नियुक्ति के लिये विचाराधीन तीन नामों से संबंधित आई.बी. एवं रॉ की रिपोर्ट उजागर कर दी?" चिदम्बरम ने आगे कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि केन्द्र ने कोलीजियम द्वारा आगे बढ़ाये गये नामों को पूरी तरह "स्वेच्छाचारिता" के आधार पर खारिज कर दिया।

पुतिन की अमेरिका को धमकी

- पुतिन ने कहा, अमेरिका के सभी टैंक रूस तबाह कर देगा।

मॉस्को, 25 जनवरी। रूस और यूक्रेन के युद्ध को अब एक साल होने जा रहा है, इसके बाद भी यह लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन एक नई रणनीति के साथ यह युद्ध फिर शुरू हो जाता है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और नाटो देश। रूस, यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है तो वहीं यूक्रेन जितने भी नाटो देश हैं उनके सहारे पूतिन की हर चाल को मात देने में जुटा है। नाटो देशों ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को सैन्य सहायता बढ़ा दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन समेत कई देशों ने यूक्रेन को आधुनिक हथियार देने का ऐलान किया है। इसमें अमेरिका का अब्राम्स टैंक, ब्रिटेन का चैलेंजर-2 टैंक और जर्मनी का लेपर्ड टैंक भी शामिल है।

वहीं, रूस ने धमकी दी है कि वह नाटो के किसी भी हथियार की तरह इन देशों के टैंकों को आसानी से नष्ट कर देगा। इस बीच पश्चिमी सैन्य विशेषज्ञों ने कहा है कि यूक्रेन को मिल रहे इन घातक हथियारों का रूसी सेना पर घातक असर हो सकता है। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन में पहले से ही पीछे हट रही है। ऐसे में यूक्रेन की सेना अत्याधुनिक टैंकों, मिसाइलों, रॉकेटों, बख्तरबंद वाहनों की मदद से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई कर सकती है।

अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी की कार्रवाइयां संकट को और बढ़ा देंगी। इन देशों का यह फैसला यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार मुहैया कराने से कहीं आगे निकल गया है।

'कर्मचारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्मचारियों की समस्त लम्बित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।

बैंच ने शिक्षक को अनुमति दी कि वे सम्बंधित अथॉरिटी से पढ़ाने व अन्य कार्यों की जिम्मेवारी निभाने की अनुमति ले। कोर्ट ने कहा कि इस सम्बंध में 30 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। पूर्व में जैकब पुलियेल बनाम भारत सरकार एवं अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने स्वास्थ्य के सम्बंध में कोई भी इलाज लेने से इन्कार कर दे।

उसने 2021 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब वह वैक्सीन लगवा चुका है।

चीन का बहिष्कार कर कड़ा संदेश देने की ज़रूरत : केजरीवाल

- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि, चीन लगातार हमें आँखें दिखा रहा है लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

नयी दिल्ली, 25 जनवरी (वार्ता) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीन का बहिष्कार करने का आ ान करते हुए कहा कि वह हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और हम उससे व्यापार बढ़ाते ही जा रहे हैं।

केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस की दिल्ली और देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हम एक तरफ 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु जैसे ढेरों नाम हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आजादी दिलाई थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के बाद की पीढ़ियों के उपर इस आजादी और जनतंत्र को मजबूत व संभाल कर कायम रखने की जिम्मेदारी दी है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से चीन हमारी सीमाओं पर हमें आंखें दिखा रहा है। आज ही देश के एक अखबार में छपा है कि चीन ने हमारे देश की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विषय है। हमारे सैनिक चीन के सैनिकों से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पूरी बहादुरी के साथ हमारे सैनिक बॉर्डर पर चीन का मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ, हमारे सैनिक बॉर्डर पर चीन का मुकाबला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ देश की सारी सरकारों और हर भारतवासी का भी फर्ज बनता है कि हम उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। हमारा भी फर्ज बनता है कि चीन को कड़ा संदेश दिया जाए कि भारतीय यह बर्दाश्त नहीं करेगा। हम चीन का बहिष्कार करें और उसको सख्त संदेश दें। 2020 में हम लोगों ने चीन से 65 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा और 2021 में 95 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। हमने 50 फीसद व्यापार बढ़ा दिया। हम तो चीन को और अमीर बनाते जा रहे हैं। उनसे और सामान खरीदते जा रहे हैं, उनको और पैसा दे रहे हैं। चीन हमारे ही पैसे से और अधिक हथियार खरीद रहा है, सैनिकों को भर्ती कर रहा है और हमारे उपर आक्रमण कर रहा है। यह तो सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ पिछले पांच-छह सालों में 12 लाख व्यापारी व उद्योगपति अपना देश छोड़कर विदेश चले गए। वह अपनी व्यवस्था और एजेंसी से परेशान होकर के भारत छोड़कर विदेश चले गए। हमने अपने व्यापारियों व उद्योगपतियों को इतना दुखी कर रखा है कि वह बहुत तंग आ चुके हैं, उनका अपने देश में धंधा मुश्किल हो गया है और भारत छोड़-छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर 12 लाख लोग भारत छोड़कर चले गए। हम अपने लोगों को भगा रहे हैं और चीन से सारा सामान आयात कर रहे हैं, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को स्वतंत्र कराया और जनतंत्र की स्थापना की।पिछले कुछ वर्षो से हम देख रहे हैं कि जनतंत्र के ऊपर भी थोड़ी-थोड़ी आंच आने लगी है।जनता और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि एक राज्य ऐसा है, जहां जनता की चुनी हुई सरकार ने ढेरों कानून पास किए, लेकिन वहां का गवर्नर कानून पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। जो कानून जनता ने पास किए, जो कानून जनता की चुनी हुई सरकार ने पास किए, क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है। क्या एक आदमी को अधिकार होना चाहिए कि वो जनता की अभिलाषा, कामनाओं और कामों को रोक दे। यह तो जनतंत्र नहीं है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में महंगाई की दर 3 फीसदी है, जबकि गुजरात में 7 फीसदी, हरियाणा में 7.8 फीसदी है, जो दिल्ली से ढाई गुना ज्यादा है। मध्यप्रदेश में महंगाई की दर 7.5 फीसदी है।

पूरे देश में सबसे सस्ती चीजें और सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, क्योंकि आज यहाँ बिजली, पानी मुफ्त है। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूलों में सारी शिक्षा मुफ्त है। दिल्ली में सारी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त है। सरकारी अस्पताल में सारा इलाज, टेस्ट, दवाइयां और ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। महिलाओं के लिए बसों का सफर मुक्त है। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त है। राशन मुफ्त है।

'कर्मचारी ...
(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कर्मचारियों की समस्त लम्बित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।
बैंच ने शिक्षक को अनुमति दी कि वे सम्बंधित अथॉरिटी से पढ़ाने व अन्य कार्यों की जिम्मेवारी निभाने की अनुमति ले। कोर्ट ने कहा कि इस सम्बंध में 30 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। पूर्व में जैकब पुलियेल बनाम भारत सरकार एवं अन्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने स्वास्थ्य के सम्बंध में कोई भी इलाज लेने से इन्कार कर दे। उसने 2021 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब वह वैक्सीन लगवा चुका है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600